रामजी राय और अन्य

बनाम

जगदीश मल्लाह (मृत) और अन्य जरिये विधिक प्रतिनिधि

4 दिसंबर, 2006

(न्यायमूर्ति डॉ अरिजीत पसायत और न्यायमूर्ति एस.एच. कपाडिया)

वाद:

स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा-प्रतिवादियों को मुकदमे की संपत्ति के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकना न्यायालय का कर्तव्य - न्यायालय को केवल यह तय करना है कि वादी के कब्जे में है या नहीं और न कि मुकदमे की संपत्ति का स्वामित्व है या नहीं - विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963-S.38।

अपीलकर्ताओं ने एक स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा इस आधार पर दायर किया, कि विवादित भूमि लंबे समय से उनके कब्जे में थी और उनके द्वारा उपयोग की गई थी, जिसमें उत्तरदाताओं को विवादित भूमि के कब्जे में हस्तक्षेप करने से और साथ ही विभिन्न घरेलू उद्देश्यों के लिए चारदीवारी के निर्माण में हस्तक्षेप करने से रोका जावे। ट्रायल कोर्ट ने

मुकदमे का फैसला सुनाया। अपीलीय अदालत ने यह कहते हुए डिक्री को रद्द कर दिया कि अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहे कि विवादित भूमि उनका स्वामित्व था और उन्होंने चारदीवारी का निर्माण किया था।

उच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा।

इस न्यायालय में अपील में अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि मुकदमा केवल स्थायी निषेधाज्ञा के लिए था, न कि स्वामित्व की घोषणा के लिए। निचली अपीलीय अदालत ने यह मानने में गलती की थी कि अपीलकर्ता विवादित भूमि पर अपना स्वामित्व साबित करने में विफल रहे थे।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया-

1. निचली अपीलीय अदालत को अपीलकर्ताओं द्वारा दायर मुकदमे को केवल इस आधार पर खारिज कर देना चाहिए था कि अपीलकर्ता यह साबित करने में असफल रहे कि विवादित भूमि पर उनका कब्जा था। विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 38 के तहत, कब्जे में हस्तक्षेप को रोकने वाला निषेधाज्ञा स्वामित्व की सुरक्षा के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा के मामले में वादी के पक्ष में अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसका कब्जा नहीं पाया गया है। जिसमें वादी का आरोप है कि उसका कब्जा है

और प्रतिवादी द्वारा धमकी दी जा रही है, वादी अपने अधिकारों की घोषणा के लिए प्रार्थना जोड़े बिना केवल निषेधाज्ञा मुकदमा करने का हकदार है।

मुल्ला का भारतीय अनुबंध और विशिष्ट राहत अधिनियम 12 वां संस्करण, पृष्ठ 28 पर भरोसा किया।

2. वर्तमान वाद केवल स्थायी निषेधाज्ञा के लिए है और इसलिए निचली अपीलीय अदालत को तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर इसे केवल इस आधार पर खारिज करना चाहिए कि अपीलकर्ता यह दिखाने में विफल रहे हैं कि उनका कब्जा था। ऐसा किया गया है लेकिन यह घोषणा करना आवश्यक नहीं था कि अपीलकर्ता मालिक नहीं हैं।

ए.एल.वी.आर. सीटी वीरप्पा चेट्टियार बनाम अरुणाचलम चेट्टी और अन्य, एआईआर (1936) मद्रास 200 का उल्लेखित है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 5353/2006

(इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 2.4.2004 की न्यायिक कार्यवाही संख्या एस.ए. संख्या 2839/1981 है।)

अपीलकर्ताओं के लिए डॉ आर.जी.टी के लिए पाडी, सुशील मिश्रा, तुषार बख्शी और नरेश बख्शी।

उत्तरदाताओं के लिए पी.के. जैन

न्यायमूर्ति कपाड़िया द्वारा निर्णय सुनाया गया

अनुमति प्रदान की गई।

वादी (यहाँ अपीलकर्ता संख्या 1) ने अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट VII की अदालत में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए सिविल वाद संख्या 202/27 प्रस्तुत किया, उक्त मुकदमे में प्रतिवादियों के खिलाफ अपीलकर्ता ने प्रतिवादियों को जमीन के कब्जे में हस्तक्षेप करने और चारदीवारी बढ़ाने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की। इस मामले में यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ताओं के पास उनके पूर्वजों के समय से एक घर था और उनका सेहन उक्त घर के दक्षिण की ओर था: अधिनियम के लागू होने से पहले भी उक्त सेहेन उनका कब्जा था। जमींदारी उन्मूलन और जी भूमि सुधार अधिनियम, 1950 और उक्त भूमि पर उनके मवेशी पालने और नांद आदि थे, जिसका उपयोग अपीलकर्ताओं द्वारा विभिन्न घरेलू उद्देश्यों के लिए किया गया था। अपीलकर्ताओं ने आगे आरोप लगाया कि विवादित भूमि बंजर भूमि थी और उन्होंने निर्माण शुरू कर दिया था।

उनके घर और सेहन के बीच एक छोटा सा रास्ता छोड़ने के बाद चारदीवारी। अपीलकर्ताओं ने आगे कहा कि वे चारदीवारी को पूरा नहीं कर सके क्योंकि उन्हें घर जाना था, बम्बई जहां वे कार्यरत थे; जब वे बंबई से गांव वापस आए तो उन्होंने पुनर्निर्माण का काम शुरू किया जिसमें उत्तरदाताओं ने बाधा डाली और इसलिए, उन्हें विवाद में भूमि के कब्जे में हस्तक्षेप करने से उत्तरदाताओं को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि चारदीवारी के निर्माण में हस्तक्षेप करने के लिए भी।

उत्तरदाताओं ने उपरोक्त आरोपों से इनकार किया। उनका तर्क था कि यह विवादित भूमि उनकी है; विवादित भूमि का उपयोग उनके द्वारा विभिन्न घरेलू उद्देश्यों के लिए किया गया था; कि वे कई वर्षों से विवादग्रस्त भूमि पर कब्ज़ा कर रहे थे; अपीलकर्ताओं के घर और विवादित भूमि के बीच एक रास्ता था: उत्तरदाताओं ने एक दीवार का निर्माण किया था जो वर्तमान मुकदमे में अपीलकर्ताओं द्वारा प्राप्त अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश के कारण पूरा नहीं किया जा सका। उत्तरदाताओं ने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता अपनी कृषि भूमि नहीं जोत रहे थे, इसलिए अपीलकर्ताओं ने अपनी कृषि भूमि दूसरों को दे दी थी। जैसा कि अपीलकर्ताओं ने दावा

किया है, विवादित भूमि पर किसी भी मवेशी या कृषि उपकरण को रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

मुद्दों को तय करने के बाद विचारण न्यायालय ने मुकदमे का फैसला सुनाया। विचारण न्यायालय ने माना कि अपीलकर्ता मालिक थे और विवादित भूमि पर उनका कब्जा था।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री से व्यथित होकर, उत्तरदाताओं ने मामले को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत में 1979 की सिविल अपील संख्या 84 के तहत अपील में पेश किया। बलिया।

निर्णय एवं आदेश दिनांक 21.9.1981 द्वारा ए.डी.जे. इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वादी अपीलकर्ता यह साबित करने में असफल रहे कि विवादित भूमि उनकी सेहन भूमि थी, अपीलकर्ता संख्या 1 ने अपने बयान में स्वीकार किया था कि एक रघुनाथ राय उनके पिता का असली भाई था; अपीलकर्ताओं और रघुनाथ राय के बीच परिवार में अलगाव हो गया था: अलगाव से पहले अपीलकर्ता और रघुनाथ राय संयुक्त थे; उस समय उनके पास एक साझा सेहन भूमि थी और उस समय अपीलकर्ता सेहन थे। जब परिवार संयुक्त था तो वह अपने घर के पूर्व की ओर था। निचली अपीलीय अदालत ने आगे पाया कि अपीलकर्ता और प्रतिवादी दोनों

विवादित भूमि को अपनी इमारत से जुड़े क्षेत्र के रूप में दावा कर रहे थे। हालाँकि, निचली अपीलीय अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि चारदीवारी का निर्माण प्रतिवादियों द्वारा किया गया था, न कि अपीलकर्ताओं द्वारा। निचली अपीलीय अदालत ने आगे पाया कि अपीलकर्ताओं की उस भूमि तक कोई सीधी पहुंच नहीं थी, क्योंकि अपीलकर्ताओं के बीच एक लेन चल रही थी विचाराधीन घर और विवादित भूमि; कि अपीलकर्ता अपने पूर्वजों के समय से विवादित भूमि को अपने सेहन के रूप में उपयोग नहीं कर रहे थे; अपीलकर्ताओं ने स्वीकार किया था कि विभाजन से पहले अपीलकर्ताओं के वर्तमान घर का उपयोग मवेशियों को रखने के लिए किया जाता था और विभाजन से पहले अपीलकर्ताओं का सेहन पूर्व की ओर था, न कि घर के दक्षिण की ओर जैसा कि अपीलकर्ताओं ने दावा किया था। निचली अपीलीय अदालत ने आगे पाया कि उत्तरदाता विवाद में भूमि का उपयोग कर रहे थे: वे विवादित भूमि पर मवेशी रख रहे थे; वे विवादित भूमि और निचली अपीलीय परिस्थितियों में चारा और अन्य कृषि उपकरण रख रहे थे! अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वाद भूमि का उपयोग प्रतिवादियों द्वारा अपने घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था और उक्त भूमि पर उनका कब्जा था। इन परिस्थितियों में, मुकदमा निचली अपील अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया था।

निचली अपीलीय अदालत द्वारा दिए गए फैसले से व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने मामले को दूसरी अपील में उच्च न्यायालय में ले जाया। आक्षेपित निर्णय द्वारा 1981 की द्वितीय अपील क्रमांक 2839 दिनांक 2.4.2004 को खारिज कर दी गई। इसलिए यह सिविल अपील है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है, निचली अपीलीय अदालत ने दिनांक 21.9.19 के फैसले के तहत अपीलकर्ताओं द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया। मुकदमे को ख़ारिज करते हुए निम्न अपीलीय अदालत ने इस प्रकार आयोजित किया:

> "जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, रिकॉर्ड पर मौजूद सभी सामग्रियों पर विचार करने पर, मुझे पता चला है कि वादी यह स्थापित करने में पूरी तरह से विफल रहा है कि विवादित भूमि कभी भी उसकी सहन भूमि के रूप में उसके कब्जे में थी। वह यह भी स्थापित करने में विफल रहा है कि निर्माण के समय तक मुकदमे की फाइलिंग की गई थी। ऐसा होने पर, वादी विवादित भूमि का मालिक साबित नहीं होता है। इसलिए, वह दावे के अनुसार कोई राहत पाने का हकदार नहीं है। परिणामस्वरूप, अपील सफल होती है और इसे लागतों के साथ अनुमति दी जानी चाहिए।" (हमारे द्वारा रेखांकित)

डॉ. आर.जी. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील पाडिया ने प्रस्तुत किया कि निचली अपीलीय अदालत और उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की है कि अपीलकर्ताओं के पास मुकदमे की भूमि (उनकी सेहन भूमि के रूप में) नहीं थी। आगे तर्क दिया गया कि सीमा दीवार का निर्माण अपीलकर्ताओं द्वारा किया जा रहा था, न कि प्रतिवादियों द्वारा। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि किसी भी घटना में निचली अपीलीय अदालत ने यह कहने में गलती की थी कि अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहे हैं कि वे विवाद भूमि के मालिक थे। यह आग्रह किया गया था कि वर्तमान मुकदमा केवल स्थायी निषेधाज्ञा के लिए था। यह आग्रह किया गया था कि अपीलकर्ताओं ने कभी भी स्वामित्व की घोषणा की मांग नहीं की थी और इसलिए, निचली अपीलीय अदालत ने यह मानने में गलती की थी कि अपीलकर्ता विवादित भूमि पर अपना स्वामित्व साबित करने में विफल रहे थे।

तथ्यों के पता चलने पर हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। समवर्ती निष्कर्षों को उलटने का कोई कारण नहीं है। हालाँकि, यह बताने के लिए पर्याप्त है कि निचली अपीलीय अदालत को केवल अपीलकर्ताओं बी द्वारा दायर मुकदमे को इस आधार पर खारिज कर देना चाहिए था कि अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहे थे कि विवादित भूमि पर उनका कब्जा था।

विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 38 के तहत। 1963 कब्जे में गड़बड़ी को रोकने वाली निषेधाज्ञा उस वादी के पक्ष में नहीं दी जाएगी जिसके पास कब्जा नहीं पाया गया है। स्वामित्व स्वामित्व की सुरक्षा पर आधारित स्थायी निषेधाज्ञा के मामले में, जिसमें वादी का आरोप है कि वह कब्जे में है, और प्रतिवादी द्वारा उसके कब्जे को धमकी दी जा रही है, वादी घोषणा के लिए प्रार्थना जोड़े बिना केवल निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा करने का हकदार है। उसके अधिकारों के बारे में। (मुल्ला का भारतीय अनुबंध और विशिष्ट राहत अधिनियम, 12 वां संस्करण, पृष्ठ 2815 देखें)

ए.एल.वी.आर. के मामले में सी.टी. वीरप्पा चेट्टियार बनाम अरुणाचलम चेट्टी और अन्य, एआईआर (1936) मद्रास 200, यह माना गया है कि केवल यह तथ्य कि शीर्षक के प्रश्न पर यह निर्णय लेने की आवश्यकता हो सकती है कि निषेधाज्ञा दी जा सकती है या नहीं, इसका कोई औचित्य नहीं है यह मानते हुए कि मुकदमा स्वामित्व की घोषणा और निषेधाज्ञा के लिए है। केवल निषेधाज्ञा के लिए ही वाद हो सकता है। वर्तमान मुकदमा केवल स्थायी निषेधाज्ञा के लिए है और इसलिए, निचली अपीलीय अदालत को इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए। इसे केवल इस आधार पर खारिज करने तक ही सीमित रखा गया कि

अपीलकर्ता यह दिखाने में असफल रहे कि उनका कब्जा था। ऐसा किया गया है लेकिन यह घोषणा करना आवश्यक नहीं था कि अपीलकर्ता मालिक नहीं हैं।

उपरोक्त स्पष्टीकरण के अधीन, अपील लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के खारिज कर दी जाती है।

डी.जी.

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।